गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BIIL AND RESOLUTION

सातवां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेय कों तथ संकल्पों सम्बन्धी समिति का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

पाकिस्तान में आपात-स्थिति की घोषणा तथा भारत-पाकिस्तान सीमा का स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : DECLARATION OF EMERGENCY IN PAKISTAN AND SITUATION ON INDIA-PAKISTAN BORDER

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिक मंत्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : सदन पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खां की उस घोषणा से अवगत है जिसके माध्यम से कल उन्होंने समूचे पाकिस्तान में आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी । उनकी यह कार्यवाही बंगला देश से विश्व का ध्यान हटाने और उस स्थिति के लिए जो उन्होंने स्वयं उत्पन्न की है, भारत को दोषी ठहराने के प्रयत्नों की पराकाष्ठा है । सैनिक शासन द्वारा जिसने गत आठ मास से बंगला देश की जनता के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा है और जो पिछले 3-4 महीनों से हमें पूर्ण युद्ध की धमकी दे रहा है, ऐसी घोषणा का अपनी जनता व विश्व को धोखा देने के अलावा और कोई अर्थ नहीं है ।

राष्ट्रपति याह्या खां के ईद-संदेश से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अन्ततः वह विश्व के अनेक नेताओं की इस सलाह पर ध्यान देने लगे हैं कि समस्या को सेना के बल पर हल न करके, उसका राजनीतिक हल निकाला जाये । हमें आशा है कि पाकिस्तान में आपातकालीन स्थिति की घोषणा राजनीतिक हल खोजने से बचने का उपाय नहीं है ।

मानसून के बाद मुक्तिबाहिनी की सफलता ने पाकिस्तान के सैनिक शासन की योजना को अस्त-व्यस्त कर दिया है । बंगला देश की मुक्ति सेना ने अपनी पूरी जनता के सहयोग से पाकिस्तानी सशस्त्र सेना को भारी क्षति पहुंचायी है और अपनी मातृ-भूमि का बड़ा भाग मुक्त करा लिया है ।

हम लगभग एक करोड़ भयभीत पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का बहुत बड़ा भार उठाये हुए हैं, जो कि पाकिस्तानी दमन से बचने के लिए भाग कर आए हैं । ये शरणार्थी सुरक्षा व सम्मान की गारंटी मिलने पर स्वदेश लौटना चाहते हैं । हमारा यह दृढ़ निश्चय है कि ये शरणार्थी उक्त परिस्थितियों के अन्तर्गत यथाशीघ्र स्वदेश लौटे ।

पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाएं हमारे सीमा क्षेत्रों पर गोलाबारी करके जीवन व संपत्ति को नुकसान पहुँचा रही है । उसकी वायुसेना ने जानबूझ कर कई बार हमारी वायुसीमा का उल्लंघन किया और एक बार तो उसका विमान श्रीनगर तक चला आया । उसके गुप्तचर और तोड़-फोड़ करने वाले ट्रेनों और पुलों को उड़ा रहे हैं । मार्च 1971 से हमने 890 घटनाओं के बारे में 66 विरोधपत्र भेजे हैं । लेकिन इन विरोधों का कोई असर नहीं हुआ । पाकिस्तान प्रचार कर

रहा है कि हम उसके साथ अघोषित युद्ध में उलझे हैं और हमने टैंकों व भारी संख्या में सेना से उस पर हमला कर दिया है, वह बिल्कुल गलत है। वास्तव में पाकिस्तान ने ही हमें पूर्ण युद्ध की धमकी दी और अपनी सशस्त्र सेनाओं को वह सीमा पर ले आया और उसने 'भारत जीतो' 'भारत को कुचलो' नारों के साथ भारत के विरुद्ध घृणा-आंदोलन शुरू कराया। इसलिये हमें भी अपनी सेनाओं को देश की एवं जनता की जान-माल की रक्षा करने के लिए रक्षात्मक मोर्चों पर तैनात कर दिया। हमारा इरादा स्थिति को भड़काने या संघर्ष शुरू करने का कभी नहीं रहा। और इसीलिए हमने अपनी सेनाओं को निर्देश दिया है कि वह आत्मरक्षा को छोड़ कर, अन्यथा सीमा पार न करे। हम 1947-48, जनवरी 1965 और अगस्त-सितम्बर 1965 के अपने अनुभवों की उपेक्षा नहीं कर सकते।

21 नवम्बर को पाकिस्तान की पैदल सेना ने, टैंकों व तोपखाने की सहायता से मुक्तिवाहिनी पर, जो बायरा के आसपास के मुक्त किये क्षेत्र पर डटी थीं, भारी हमला बोल दिया। पाकिस्तान की बख्तर बंद सेना हमारी सीमा की ओर बढ़ती आयी जिससे हमारे सुरक्षा मोर्चों को खतरा पैदा हो गया। उनके गोले हमारे क्षेत्र में गिरे जिससे अनेक व्यक्ति घायल हो गये। हमारे स्थानीय सैनिक कमांडर ने पाक हमले को विफल करने के लिए उपयुक्त कदम उठाया जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान के 13 टैंक नष्ट हो गये।

नवम्बर को पाकिस्तान के चार सैबर जेटों ने हमारे ठिकानों पर हमला करने का प्रयत्न किया। हमारे नैट विमानों ने इनका भारतीय वायु-सीमा के अन्दर मुकाबला किया और तीन सैबर जेट विमानों को मार गिराया। दो पाक विमान चालकों को, जो पैराशूट से उतर आये थे, भारतीय क्षेत्र में ही बंदी बना लिया गया। किन्तु हम इसे विशुद्धतः स्थानीय कार्रवाई मानते हैं।

हालांकि पाकिस्तान ने आपत्कालीन स्थिति की घोषणा की है, हम तब तक ऐसा कदम नहीं उठायेंगे जब तक कि पाकिस्तान की आक्रामक कार्रवाइयां राष्ट्रीय हित में हमें ऐसा कदम उठाने से मजबूर नहीं करेंगी। इस बीच देश दृढ़ता कायम रखे। हमारी साहसी सेनाएं और जनता पाकिस्तान के किसी भी कदम का उपयुक्त उत्तर देगीं। पाकिस्तान के शासकों को वह महसूस करना चाहिए कि शांति का रास्ता—शांतिपूर्वक बातों व समझौते का—युद्ध जनतंत्र व स्वाधीनता को कुचलने के रास्ते से कहीं अधिक हितकर है।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

छठा प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा कार्यमंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन से, जो 23 नवम्बर 1971 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है।